पंजाब सरकार

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री, पंजाब

द्वारा

पंजाब विधान सभा में

वर्ष 2025-26 का
बजट पेश करते समय दिया गया

भाषण

26 मार्च, 2025 चण्डीगढ़

बजट 2025-26

हरपाल सिंह चीमा

वित्तीय मंत्री

का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं बड़ी विनम्रता और गहरी प्रतिबद्धता के साथ इस प्रतिष्ठित सदन में आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश करने जा रहा हूँ। मेरे लिए यह गौरव का क्षण है कि मैं एक बार फिर इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष खड़ा हूं, जहां मैं पिछले तीन वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा की तस्वीर पेश कर रहा हूं तथा भविष्य के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहा हूं, जो पंजाब और इसके लोगों के लिए आशाओं और संभावनाओं से भरी हुई है।

2. सबसे पहले, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका दूरदर्शी नेतृत्व पिछले तीन वर्षों में पंजाब की उल्लेखनीय प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। हमारे लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने हमें विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने में मार्गदर्शन दिया है तथा समृद्ध और सशक्त पंजाब के लिए मजबूत नींव रखी है।

3. एक समय था जब पंजाब भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। भारत में जो भी बेहतरीन चीजें होती थीं, वे पंजाब में ही होती थीं। हरित क्रांति यहीं हुई थी। लुधियाना को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यह साइकिल उद्योग का भी केंद्र बन गया। जालंधर खेल के सामान की वैश्विक राजधानी बन गया। 1980 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ऊपर थी।

4. लेकिन पिछले 4 दशकों में इन सभी पार्टियों ने पंजाब को पूरी तरह से लूटा और बर्बाद कर दिया है। आज पंजाब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्यों की सूची में 15वें नंबर पर है। इन पार्टियों ने पंजाब को जो एकमात्र विरासत छोड़ी है, वह है - उड़ता पंजाब।

5. 2022 में पंजाब की जनता ने 'बदलाव' के लिए वोट दिए हैं। उन्होंने पंजाब के इतिहास में आप और मुख्य मंत्री भगवंत मान को सबसे बेमिसाल जनादेश दिया। तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने उस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

6. हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए साहसिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने 90% घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। आम आदमी क्लीनिकों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मुफ़्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त की हैं, जिससे सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित हुई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ़ हमारी निरंतर लड़ाई के परिणामस्वरूप 817 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया है, जो स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए, हमने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 144 उच्च तकनीक वाले वाहनों के साथ सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। इसके अलावा, 406 सरकारी सेवाओं की घर-द्वार डिलीवरी ने शासन को अधिक सुलभ और कुशल बनाकर नागरिकों को सशक्त बनाया है, जबकि 1.5 लाख लोगों ने 'सी.एम. दी योगशाला' पहल का लाभ उठाया है, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिला है।

7. समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता समाज के कमजोर वर्गों को दी गई ₹16,848 करोड़ की वित्तीय सहायता में दिखाई देती है, जबकि पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ₹96,836 करोड़ का निवेश सुरक्षित किया है। शिक्षा क्षेत्र में, हमने

118 स्कूल आफ़ एमिनेंस स्थापित किए हैं तथा सिंगापुर और फिनलैंड में उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिससे हमारे शिक्षकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हमने 15,947 जल चैनलों को पुनर्जीवित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि नहर का पानी सिंचाई के लिए अंतिम छोर तक स्थित खेतों तक पहुंचे, जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल सके और पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

8. ये परिवर्तनकारी पहल सामूहिक रूप से हमारी सरकार के 'रंगला पंजाब' बनाने के दृढ़ संकल्प को वास्तविक रूप देती हैं - एक ऐसा पंजाब जो समावेशी, प्रगतिशील और सभी के लिए अवसरों से भरपूर हो और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष का बजट उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसमें यह परिवर्तन पंजाब के हर गांव, हर शहर - बड़े या छोटे - को छूने वाला है। इसीलिए मैं इस बजट की थीम "बदलता पंजाब" रखने जा रहा हूँ।

बजट वित्तीय वर्ष 2025-26

माननीय अध्यक्ष महोदय,

9. आंकड़ा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर है, तथा चालू वर्ष में इसने प्रभावशाली 9% वृद्धि दर्ज की है। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्य पर ₹8,09,538 करोड़ तक पहुंच गया है। भविष्य में यह गति जारी रहने की उम्मीद है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में चालू कीमत पर जीएसडीपी में 10% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो ₹8,91,301 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

10. जैसा कि हमने अपने पहले बजट में वादा किया था, हमने पंजाब की बिगड़ती वित्तीय सेहत को सुधारने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि हमें विरासत में एक कमजोर वित्तीय

स्थिति मिली थी। मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लगातार तीसरे वर्ष भी अपनी प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं। पंजाब के अपने कर राजस्व ने चालू वर्ष में भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है, जो फ़रवरी, 2025 तक 14% तक बढ़ गई है।

11. मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹2,36,080 करोड़ का बजट व्यय प्रस्तावित करता हूँ। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.51% और 3.84% रहने का अनुमान है जो पिछले आंकड़े से बेहतर हुआ है। इससे पता चलता है कि राज्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह पर है।

12. अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रस्तावित “बदलता पंजाब” रोडमैप को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

युद्ध नशे दे विरुद्ध

13. अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पंजाब की प्रगति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा नशे की समस्या है। नशे के कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। तीन वर्ष पहले जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने राजनेताओं और ड्रग माफियाओं के बीच गठजोड़ को तोड़ दिया है, जो पिछले दो दशकों से सभी दलों के शासनकाल में फल-फूल रहा था। यह स्पष्ट है कि इस पैमाने की समस्या के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने 1 मार्च, 2025 से "युद्ध नशे दे विरुद्ध" लॉन्च किया। सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार पांच नदियों की इस महान भूमि से इस समस्या को जड़ से खत्म करने का इरादा रखती है। परिणाम खुद अपनी कहानी कहते हैं। इस अभियान के मात्र कुछ दिनों में पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक

सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुल 2,136 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 3,816 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मैं पंजाब के लोगों से वादा करता हूँ कि यह तो बस शुरुआत है। हम समाज के हर वर्ग को "युद्ध नशे दे विरुद्ध" अभियान में शामिल करेंगे और इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक पंजाब से नशे की समस्या जड़ से समाप्त नहीं हो जाती।

14. अध्यक्ष महोदय, पंजाब में आने वाली अधिकांश नशीली दवाएं सीमा पार से आती हैं। नशीली दवाओं और हथियारों की सीमा पार से तस्करी रोकना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा 50 किलोमीटर का क्षेत्र बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह समस्या अभी भी व्याप्त है। अब हमने सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए दो पहल करते हुए बीएसएफ के प्रयासों को पूरक बनाने का फैसला किया है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पंजाब सरकार सीमा पर बीएसएफ के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करेगी। इन होमगार्डों का चयन सबसे दृढ़ निश्चयी पंजाबी युवाओं में से किया जाएगा, जो पंजाब के भविष्य की रक्षा पर पैनी नज़र रखेंगे। दूसरा, हमारी सरकार दुनिया की सबसे उन्नत और प्रभावी एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाएगी, जो पंजाब के अंदर ड्रग्स और हथियार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हाईटेक सीमा पार ड्रोन को ट्रैक और बेअसर कर सकती है। हमने पहले ही अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण शुरू कर दिया है और आने वाले वर्ष में सीमा पर एंटी-ड्रोन प्रणालियाँ तैनात करेंगे। मैं अगले वर्ष इन पहलों के लिए ₹110 करोड़ का बजट प्रावधान कर रहा हूँ।

15. हम ड्रग्स के खिलाफ़ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए एक और ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। हमें इस लड़ाई को सिर्फ़ ताकत और हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और विश्लेषण के ज़रिए वैज्ञानिक तरीके से भी लड़ना है। हमने अगले वर्ष पंजाब में पहली बार

"ड्रग सेंसस" करने का फैसला किया है। यह सेंसस पंजाब के हर घर को कवर करेगा और पंजाब के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अलावा ड्रग्स के प्रचलन, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग आदि को समझने के लिए डेटा एकत्र करेगा। हम इस डेटा का उपयोग अगले 1-2 वर्षों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति बनाने के लिए करेंगे। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पहल पर ₹150 करोड़ खरच करने का प्रस्ताव रखती है।

16. हमारी सरकार नशीले पदार्थों के मुद्दे के साथ-साथ गैंगस्टरों पर नकेल कसने और पंजाब में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के मामले में बहुत सख्त रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी पुलिस किसी भी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया करने और अपराधियों को समय पर पकड़ने के लिए अच्छी तरह से लैस है, हम आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों (ईआरवी) के बेड़े को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिस के तहत '112' पर की गई आपातकालीन कॉल का जवाब दिया जाएगा। वर्तमान में, पंजाब पुलिस 258 समर्पित ईआरवी का बेड़ा संचालित करती है, जिसके कारण संकट कॉल पर औसत प्रतिक्रिया समय 30 मिनट तक हो जाता है। अगले वर्ष, हमने 758 चार पहिया वाहन और 916 दो पहिया वाहन खरीदने और उन्हें ईआरवी के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है, जिससे हमारे बेड़े का आकार प्रभावी रूप से 6 गुना बढ़ जाएगा। इससे हम एमरजैंसी कॉलों पर औसत रिसपांस समय को घटाकर 8 मिनट कर देंगे, जो देश में सबसे कम होगा। इसके अलावा, हम मोहाली में 'डायल 112' प्रतिक्रिया टीम के लिए अत्याधुनिक मुख्यालय का निर्माण करेंगे, जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं से सुसज्जित होगा। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन खरीदने के लिए ₹125 करोड़ और नए 'डायल 112' मुख्यालयों के निर्माण के लिए ₹53 करोड़ के फ़ंड की घोषणा करता हूं।

खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब

17. एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब हम "युद्ध नशे दे विरुद्ध" अभियान के तहत ड्रग माफिया पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्रवाई करेंगे तो हम अपने युवाओं को इसमें कैसे शामिल करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इसका उत्तर खेलों में छिपा है। पंजाब हमेशा से ही चैंपियनों की भूमि रही है। हमारे युवाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना नाम चमकाने की प्रतिभा और जुनून है। पंजाब के भविष्य के सुपरस्टारों को तैयार करने के लिए, हम राज्य के इतिहास में पहली बार एक मेगा स्पोर्ट्स पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है "खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब"। भगवंत मान सरकार जी का यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले वर्ष में हमारे प्रयास पंजाब को खेल उत्कृष्टता का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

18. अध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में बच्चों और युवाओं में खेल की असीमित प्रतिभा है। लेकिन उनके पास उचित खेल के मैदान या साजो-सामान तक नहीं हैं। “खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल के तहत, हमारी सरकार ने पंजाब के हर गांव में खेल के मैदान और इनडोर जिम उपलब्ध कराकर जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुणवत्तायुक्त खेल के मैदानों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो समतल हों, जिनमें उचित रनिंग ट्रैक, बच्चों के लिए अलग खेल क्षेत्र और सोलर लाइटिंग की व्यवस्था हो। ये खेल के मैदान हमारे गांव में जीवंत स्थानों के रूप में कार्य करेंगे, जो विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को एक साथ और करीब लाएंगे। वे हमें एक घनिष्ठ, स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने में मदद करेंगे, जो ‘बदलता पंजाब’ के पीछे का दृष्टिकोण भी है। हम प्रत्येक गांव के खेल के मैदान में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेल जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। उदाहरण के लिए, तरनतारन जिले में वॉलीबॉल की बहुत मांग है। पिछले 15 दिनों में ही हमने

पायलट आधार पर तरनतारन के गांवों में 87 वॉलीबॉल खेल के मैदान बनाए हैं। हमारे खेल विभाग ने प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों की मैपिंग की है और आने वाले वर्ष में पूरे पंजाब में ऐसे ग्रामीण खेल के मैदान बनाए जाएंगे। हम पूरे पंजाब में 3,000 इनडोर जिम भी स्थापित करेंगे ताकि गांवों में रहने वाले हमारे युवाओं को फिट रहने और प्रतिस्पर्धी खेलों में भाग लेने के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा मिल सके।

19. "खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब" पहल के तहत, पंजाब सरकार 13 मौजूदा सेंटर आफ़ एक्सीलेंस को भी उन्नत और आधुनिक बनाएगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले पंजाब के सभी चैंपियन एथलीटों के लिए केंद्र बन जाएंगे।

20. भगवंत मान सरकार के "खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब" के सपने को साकार करने के लिए, मैं आगामी वर्ष में खेल विभाग को ₹979 करोड़ के ऐतिहासिक फ़ंड की घोषणा कर रहा हूं, जो पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फ़ंड है। यह राशि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों द्वारा 2012 से 2022 तक 10 वर्षों में खेलों पर संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि से भी अधिक है। यह अपने आप में पंजाब में खेलों के प्रति हमारी सरकार के दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

अध्यक्ष महोदय,

"एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक समृद्ध समाज की नींव है - क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम फलते-फूलते हैं, और जब हम फलते-फूलते हैं, तो हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं।"

21. हमारा मानना है कि निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए - चाहे वे अमीर हों या गरीब। यह

पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी कोई भी सरकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित नहीं कर पाई है। लेकिन पंजाब अब और इंतजार नहीं करेगा। स्वास्थ्य हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है, और हम इस अंतर को हमेशा के लिए पाटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति की है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवाएं और मुफ्त परीक्षण प्रदान करते हैं। आम आदमी क्लिनिकों में प्रतिदिन 70,000 से अधिक लोग मुफ्त उपचार प्राप्त करते हैं और अब तक 3 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹268 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है।

22. हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी का सपना है कि पंजाब के लोगों को तृतीयक देखभाल अर्थात अस्पताल में इलाज मुफ्त और सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हो। अब तक पंजाब के 45 लाख परिवार सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में नामांकित हैं, जिनमें से 16 लाख परिवार केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत और शेष 29 लाख परिवार पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री सरबत्त सेहत बीमा योजना' के अंतर्गत आते हैं। इन योजनाओं में पूरे परिवार के लिए बीमा कवरेज केवल ₹5 लाख प्रति वर्ष था। अध्यक्ष महोदय, आज मैं पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा कर रहा हूं।

23. पंजाब के इतिहास में पहली बार सरदार भगवंत मान सरकार ने आगामी वर्ष में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है ताकि इसे सार्वभौमिक बनाया जा सके और पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर किया जा सके। इसमें कोई रोक या भेदभाव नहीं होगा - ग्रामीण हो या शहरी, अमीर हो या गरीब - हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि हम पंजाब के सभी परिवारों के

लिए बीमा कवर को बढ़ाकर ₹10 लाख प्रतिवर्ष कर रहे हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राज्य सरकार से ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सरबत्त सेहत बीमा योजना के तहत आने वाले सभी परिवारों को अगले वर्ष एक 'सेहत कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से वे पंजाब भर के अस्पतालों में ₹10 लाख तक का कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक पहल पंजाब के प्रत्येक परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएंप्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी अपने स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के बीच चयन न करना पड़े। मैंने इस मकसद के लिए ₹778 करोड़ का प्रावधान किया है।

24. दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार प्रदान करने और मददगारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फरिश्ते' योजना को ₹10 करोड़ दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 5,598 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो चालू वर्ष से 10% अधिक है।

ग्रामीण विकास: बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब

25. हमारी सरकार मानती है कि पिंड पंजाब की आत्मा और दिल हैं। दुनिया भर में जब कोई पंजाब के बारे में सोचता है तो सबसे पहले हमारे खेत और हमारे गांव याद आते हैं। इसलिए पंजाब का विकास हमारे गांवों के बदलाव के बिना अधूरा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाला वर्ष ग्रामीण पंजाब के पुनरुत्थान का वर्ष होगा। अपने गांवों में जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, हम अगले दो वर्षों में राज्य भर के सभी 12,581 गांवों में बुनियादी ढांचे के उत्थान के लिए एक व्यापक पैकेज पेश कर रहे हैं। इसे "बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब" पहल कहा जाएगा। आने वाले वर्ष में पंजाब के सभी गांवों

में निम्नलिखित पांच कार्य किए जाएंगे:

a. गांव के तालाबों की सफाई और पुनरुद्धार
b. सीचेवाल-थापर मॉडल और अन्य लागत प्रभावी मॉडलों के अनुसार सीवेज उपचार प्रणालियों की स्थापना
c. नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए नेहरी खाल को बहाल करना
d. ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण
e. मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाना

26. अध्यक्ष महोदय, मैंने ऊपर जिन कार्यों का ज़िक्र किया है, उनमें से कई कार्य पंजाब के गांवों में दशकों से नहीं किए गए हैं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अगले वर्ष इस पहल के तहत कुल ₹3,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

27. पंजाब के सभी गांवों की ग्रामीण कनेक्टिविटी सुनिश्चित किए बिना हम 'बदलता पंजाब' की आकांक्षा नहीं कर सकते। आज मैं पंजाब के लोगों से एक वादा करना चाहता हूँ। अगले वर्ष हम पंजाब के सभी टूटे हुए ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण करने जा रहे हैं, जो हमारे दूर-दराज के गांवों को एक-दूसरे और पास के कस्बों और शहरों से जोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि एक वर्ष के बाद एक भी लिंक रोड टूटी हुई न रहे। इसे हासिल करने के लिए हम कुल 18,944 किलोमीटर ग्रामीण लिंक रोड का निर्माण और अपग्रेडेशन करेंगे - जो मेरा मानना है कि पंजाब के इतिहास में एक वर्ष में किए जाने वाले कार्य का एक और रिकॉर्ड होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, हमारे कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में तेजी आएगी और पंजाब की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में नई ऊर्जा का संचार होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन कार्यक्रम पर ₹2,873 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

रंगला पंजाब विकास स्कीम

28. अध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोगों ने हमारे 'रंगला पंजाब' के दृष्टिकोण के कारण 2022 में आप सरकार को ऐतिहासिक जनादेश दिया। हमारी सरकार का हर एक दिन पंजाब के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रहा है। आज, हम प्रत्येक जिले में 'रंगला पंजाब विकास योजना' की घोषणा के साथ इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसे उस जिले के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय रोजमर्रा की विकासात्मक जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम का प्रबंधन डिप्टी कमिशनरों (डी.सी.) द्वारा किया जाएगा तथा इसे विधायकों, सामुदायिक संगठनों, नागरिक समूहों और जनहितैषी नागरिकों की सिफारिशों के आधार पर खर्च किया जाएगा। यह स्कीम हमारे सभी जिलों में सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों और पुलों का निर्माण और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, जल, स्वच्छता आदि में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में बहुत सहायक होगा। मैं बजट में 'रंगला पंजाब विकास स्कीम' के लिए ₹585 करोड़ (प्रति हलका ₹5 करोड़) जारी कर रहा हूं।

शहरी विकास

29. अध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोग पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं। वे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और पहली चीज जो वे देखते हैं वह यह है कि उनकी सड़कें बहुत अच्छी तरह से डिजाइन और निर्मित हैं, लेकिन पंजाब के हमारे शहरों या फ़िर कहें कि पूरे भारत के शहरों के बारे में यही सच नहीं है। विदेशों में हम जो सड़कें देखते हैं, वे उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, उन पर स्पष्ट लेन चिह्न होते हैं, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बाधा-मुक्त स्थान होता है, चारों ओर हरियाली और खूबसूरती होती है तथा अन्य सभी सुविधाओं, जैसे बेंच, स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड आदि के लिए पर्याप्त प्रबंध होते हैं। हममें से कई लोग सोचते हैं कि हमारे शहरों में भी यही सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा

सकती। भारत में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं, लेकिन हमारी सड़कें इतनी खराब क्यों दिखती हैं? इसका जवाब आसान है: "न नीयत थी, न नीति।"

30. मैं बहुत गर्व के साथ घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार ने पंजाब के शहरों में विश्व स्तरीय सड़कें बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पहले चरण में, हम अगले वर्ष चार शहरों - लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मोहाली में लगभग 50 किलोमीटर लंबी विश्व स्तरीय सड़कें बनाएंगे। इनमें शहरों की सबसे प्रमुख सड़कें शामिल होंगी, जहाँ स्थानीय निवासी और पर्यटक अक्सर आते-जाते हैं।

31. हम इन सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन करने के लिए पंजाब और भारत के शीर्ष वास्तुकारों की सेवाएं लेंगे और तत्पश्चात ठेकेदारों को नियुक्त करेंगे, जो इन सड़कों का निर्माण और 10 वर्षों की अवधि तक रखरखाव भी करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक सड़क के लिए चार गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी:

a. सबसे पहले, सड़कों को फिर से डिजाइन किया जाएगा और फिर से बिछाया जाएगा ताकि लेन की चौड़ाई एक समान हो और यातायात की अड़चनें दूर हों। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन पर उचित लेन मार्किंग की जाएगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर 3 महीने में उन्हें फिर से रंगा जाए।
b. दूसरा, हम बाधा-मुक्त, सर्वसुलभ और सौंदर्यपरक फुटपाथ का निर्माण करेंगे ताकि पैदल यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। सड़कों के मध्य किनारों की भी मरम्मत की जाएगी। प्रत्येक सड़क पर फुटपाथ और मध्य किनारों के लिए अनुकूलित भूनिर्माण/बागवानी योजना तैयार की जाएगी ताकि विश्व स्तरीय मुकाबले को हों और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी खुला पैच न छोड़ा जाए जिससे सड़क पर धूल और वायु प्रदूषण न हो।
c. तीसरा, हमारी सड़कों पर बहुत सी सेवाएं बेतरतीब ढंग से बिछाई गई हैं, चाहे वह बिजली की लाइनें हों, स्ट्रीट लाइटें हों, जल आपूर्ति लाइनें हों, बस स्टैंड हों,

पेड़ आदि हों, जो लोगों और वाहनों के आवागमन में बाधा डालते हैं। हम सभी सेवाओं की अलाइनमेंट सुनिश्चित करेंगे ताकि वे सड़को और गलीयों पर सौंदर्यपूर्ण और समान रूप से उपलब्ध हों।

d. चौथा है रखरखाव। हम ठेकेदार की जवाबदेही तय करेंगे कि वह इस बुनियादी ढांचे को 10 वर्ष तक बनाए रखे। किसी भी मरम्मत के मामले में, शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर कार्य किया जाएगा। हम विश्व स्तरीय उपकरणों का उपयोग करके इन सड़कों की नियमित और मशीनीकृत सफाई भी सुनिश्चित करेंगे ताकि 10 वर्षों तक उन की सुंदरता बनी रहे।

32. पहले वर्ष के लिए इन सड़कों की कुल परियोजना लागत ₹140 करोड़ होने का अनुमान है, और हमने इसके लिए आवश्यक आवंटन सुनिश्चित कर लिया है।

33. इन चार शहरों में सड़कों को अपग्रेड करने के अलावा, हम यह भी मानते हैं कि पंजाब की लगभग 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है - जो पंजाब के 166 कस्बों और शहरों में फैली हुई है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो। अगले वर्ष, हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रयास करेंगे कि पंजाब के सभी 166 कस्बों और शहरों में पांच आवश्यक नगरपालिका सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जाएं: अर्थात स्वच्छता, जल आपूर्ति, सीवेज, सड़कें और स्ट्रीट लाइटें। मैं इस पहल के लिए पंजाब नगर विकास निधि के अंतर्गत ₹225 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

34. एक कुशल, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 347 ई-बसें खरीदेगी, जिससे पंजाब के शहरों में टिकाऊ और सुलभ शहरी गतिशीलता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन किया गया है।

35. शहरी प्रशासन, वित्तीय और अमृतसर और लुधियाना शहर के नागरिकों को जल सेवाए प्रदान करने के लिए पंजाब नगरपालिका सेवा सुधार परियोजना (PMSIP) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹300 करोड़ का आवंटन किया गया है।

36. हाऊसिंग एवं शहरी स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹5,983 करोड़ के बजट का प्रावधान करता हूँ।

बिजली

37. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल) ने अपनी परिचालन दक्षता और सेवा वितरण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने बेहतर प्रदर्शन को दर्शाते हुए, पीएसपीसीएल अब राज्य विद्युत वितरण कंपनियों में 7वें स्थान पर है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, निगम को पिछले वर्ष के ग्रेड "बी" से ग्रेड "ए" में अपग्रेड किया गया है। इस प्रगति का श्रेय समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियों में 11.26% से 10.96% तक की कमी तथा लागत-आपूर्ति और राजस्व अंतर में प्रति यूनिट में 25 पैसे कम होने को दिया जाता है। ये प्रगति पंजाब के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने और उद्योगों, व्यवसायों और घरों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

38. अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे कस्बे और गांव अंधेरे में डूबे रहेंगे तो 'बदलता पंजाब' का सपना पूरा नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारे कई गांवों में उचित स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने "मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना" शुरू करने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से हम अगले वर्ष पूरे पंजाब में 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। हम इन स्ट्रीट लाइट्स को लगाने के लिए एक बहुत ही नवीन मॉडल का उपयोग करेंगे। महंगे खंभे लगाने के बजाय, हम इन स्ट्रीट लाइट्स को

लोगों के घरों के बाहर लगाएंगे और उनके घरेलू कनेक्शन से बिजली लेंगे। इन घरों के बिजली बिलों में से खपत हुई यूनिटों की कटौती की जाएगी, और साथ ही वे अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट होने से सुरक्षित महसूस करेंगे। मैं आगामी वर्ष के लिए "मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना" के लिए ₹115 करोड़ का प्रावधान कर रहा हूँ।

39. बिजली ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, चालू वर्ष में, राज्य ने 16 नए 66 केवी सबस्टेशन चालू किए हैं, 106 बिजली ट्रांसफार्मर संवर्धित किए हैं और 1,500 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं। रोपड़ और गुरदासपुर में दो 400 केवी सबस्टेशनों के चालू होने के साथ-साथ प्रमुख ट्रांसमिशन नोड्स पर बहु-क्षमता उन्नयन से पंजाब की बिजली विश्वसनीयता काफी मजबूत हुई है।

40. मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ₹7,614 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं।

उद्योग और वाणिज्य

41. महोदय, पंजाब को आमतौर पर कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान लगातार बढ़ा है। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था में उद्योग का हिस्सा कृषि के बराबर यानी 27% है। पिछली सरकारों के कुशासन के बावजूद हम यह वृद्धि कर पाए हैं, जिन्होंने उद्योग को केवल जबरन वसूली के स्रोत के रूप में देखा है। यह स्पष्ट है कि अगर पंजाब के उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के खिलाफ जीवित रहना है और आगे बढ़ना है तो उसे ऊर्जा के नए स्रोत की आवश्यकता है। हमें पंजाब में लाखों बड़े और छोटे नए व्यवसायों के लिए उपयुक्त ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ पैदा करने का यही एकमात्र तरीका है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद एक नई औद्योगिक नीति लाएगी। मैं पंजाब और पूरे देश के

सभी उद्योगपतियों और उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी नई औद्योगिक नीति भारत में सर्वोत्तम होगी और पंजाब में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रगतिशील माहौल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

42. अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसे निर्णय की घोषणा करूंगा जो वास्तव में पंजाब के उद्योग के लिए भगवंत मान सरकार की दूरदर्शिता के पैमाने को दर्शाता है। हमने विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अगले वर्ष ₹250 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन करने का निर्णय लिया है, जो पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए केवल ₹53 करोड़ खर्च किए थे और उससे पहले अकाली-भाजपा सरकार ने पांच वर्ष में एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। यह स्पष्ट तुलना दर्शाती है कि यह केवल यही सरकार है जो वास्तव में पंजाब में उद्योग की प्रगति और समृद्धि के प्रति संवेदनशील है।

43. राष्ट्रीय एकता को और बढ़ावा देने तथा पंजाब की औद्योगिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए, राज्य ने अमृतसर में यूनिटी मॉल के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस मॉल में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और पंजाब के 23 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉल होंगे, जो कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में लाने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए ₹80 करोड़ का आवंटन किया गया है।

44. हमारे एम.एस.एम.ई पंजाब के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बने हुए हैं। रेज़िंग एंड एक्सेलरेटिंग एम.एस.एम.ई परफ़ार्मेंस (RAMP) योजना के तहत, राज्य छोटे उद्यमों के लिए बाजार पहुंच, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ाने के लिए ₹120 करोड़ की परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, पंजाब अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला और मोहाली सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्रों (टीईसी)

की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रहा है।

45. मैंने ₹3,426 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली सब्सिडी भी शामिल है। मैं लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा ऑटो पार्ट्स एवं हस्त उपकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.ए.एच.टी) के अपग्रेडेशन के लिए ₹10 करोड़ के विशेष आवंटन का भी प्रस्ताव रखता हूं।

सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी और सेवा केंद्र:

46. अध्यक्ष महोदय, हर पंजाबी को भ्रष्टाचार मुक्त और परेशानी मुक्त शासन देना हमारी सरकार का मुख्य मिशन है। हमने दिसंबर 2023 में 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' योजना की शुरुआत करके इस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई थी। आज़ादी के बाद पहली बार पंजाब के लोगों को यह करिशमा देखने को मिला कि उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ़्तर नहीं जाना पड़ेगा। इसके बजाय, वे बस 1076 नंबर पर कॉल कर सकते थे और एक 'सेवा सहायक' उनके घर आकर बिना किसी भ्रष्टाचार के उनका काम करेगा। हमने 2023 में 43 सेवाओं के साथ इस सेवा को लॉन्च किया और पिछले महीने तक, इस का विस्तार हमने 29 और विभागों में 406 सेवाओं तक करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। आने वाले वर्ष में, हम और भी अधिक सेवाओं को कवर करने के लिए 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' योजना की पहुँच का विस्तार करना जारी रखेंगे। हालांकि यह योजना पहले से ही बहुत लोकप्रिय है, लेकिन हमें यह फीडबैक मिला है कि नागरिकों के द्वार पर कोई भी सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए 'सेवा सहायक' द्वारा लिया जाने वाला ₹120 का सरविस शुल्क कुछ लोगों के लिए दे पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, हमारा दृढ़ विश्वास है कि सरकारी सेवाओं की डोर सटैप डिलवरी कोई विशेश सुविधा नहीं है - यह हर किसी का अधिकार है। किसी के लिए भी सुविधा और सामर्थ्य के बीच चयन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए, इस वर्ष से हम सरकारी सेवाओं की डोर सटैप डिलवरी प्राप्त करने की लागत ₹120 से घटाकर केवल ₹50 कर रहे हैं। प्रदान की गई

प्रत्येक सेवा के लिए शेष ₹70, पंजाब सरकार वहन करेगी।

47. पंजाब सरकार घर-घर जाकर सेवाएं देने के साथ-साथ 541 सेवा केंद्र भी चलाती है, जो 438 सेवाएं प्रदान करते हैं। हर दिन, पंजाब भर में लगभग 30,000 लोग इन सेवा केंद्रों पर आते हैं। हमारी सरकार उन सभी नागरिकों की सुविधा और आराम का ध्यान रखती है जो सेवा केन्द्रों तक जाते हैं, इसलिए सरकार ने सेवा केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को उन्नत और आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सेवा केन्द्र को आधुनिक रूप दिया जाए, जिसमें पूरा वर्ष आराम के लिए एयर कंडीशनर-कम-हीटिंग सिस्टम, बैठने की खुली और आरामदायक जगह, उचित प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल संकेत चिन्ह हों।

सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों का कल्याण

48. अध्यक्ष महोदय, 'बदलता पंजाब' में सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना है। अनुसूचित जाति के हमारे भाई-बहनों के लिए एक वास्तविक मुद्दा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम (पी.एस.सी.एफ.सी) से लिए गए ऋणों पर चूक का मामला है। हालांकि ऋण लेने वाले अधिकांश लोगों ने इसे वापस कर दिया है, फिर भी कुछ वैध कारण जैसे लाभार्थी का व्यवसाय विफल हो जाना, लाभार्थी की मृत्यु हो जाना तथा परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य न होना, लाभार्थी के घर में किसी अन्य सदस्य का लम्बे समय तक बीमार रहना या आय का कोई अन्य स्रोत न होना या किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाना आदि के चलते कुछ लाभार्थी ऋण वापस नहीं कर पाए हैं। कुछ मामलों में, परिवारों को ऋण चुकाने के लिए अपना घर और संपत्ति बेचनी पड़ी है, जिससे वे गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं। हमारी सरकार ने इस स्थिति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है और मैं आज पी.एस.सी.एफ.सी के माध्यम से 31.03.2020 तक लिए गए सभी ऋणों को माफ करने की घोषणा करना चाहूंगा। इस

ऋण माफी कार्यक्रम से कुल 4,650 व्यक्ति लाभान्वित होंगे और उन्हें अपना जीवन पुनः समृद्ध बनाने का अवसर मिलेगा।

49. हमारी सरकार जीवन के हर स्तर पर नागरिकों के उत्थान तथा समावेशी समर्थन, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹9,340 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक व्यापक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी और इसमें बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹6,175 करोड़ शामिल हैं।

50. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पोषण एवं आई.सी.डी.एस. आबंटन में योजना के लिए ₹1,177 करोड़, आशीर्वाद योजना के लिए ₹360 करोड़, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए ₹262 करोड़ और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ₹170 करोड़ शामिल हैं।

51. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष पंजाब में महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा सुविधा का उपयोग करके राज्य में 12 करोड़ से अधिक यात्राओं का लाभ उठाया है, जिसके लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ₹450 करोड़ प्रदान किए हैं। इस सेवा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

52. हाशियग्रसत- अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और सभी दलित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता में - हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) को ₹13,987 करोड़ आवंटित किए हैं, जो राज्य के कुल विकास बजट का 34% है।

कृषि एवं किसान कल्याण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

53. हमारी सरकार ने हमेशा किसान-प्रथम दृष्टिकोण को अपनाया है, और किसानों की उचित मांगों के समर्थन में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही है। इस वर्ष का बजट किसानों की आय बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपाय पेश करके उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि कृषि एक टिकाऊ और लाभदायक उद्यम बन सके। लक्षित नीतियों, वित्तीय सहायता और नवीन पहलों के माध्यम से, हम अपने कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी समृद्धि को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं।

54. अगले वित्तीय वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹14,524 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है।

55. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, खरीफ मक्का फसल के लिए बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर नामक तीन जिलों को कवर करते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु लगभग 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र को धान से खरीफ मक्का में विविधीकृत किया जाएगा। खरीफ मक्का की खेती करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹17,500/- की सब्सिडी मिलेगी। इस परियोजना से लगभग 30,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, फसल विविधीकरण के उद्देश्य से विभिन्न अन्य पहलों के लिए ₹115 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

56. कृषि विस्तार, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, बागवानी को बढ़ावा देने, बीज विकास, खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने और डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कृषोन्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹149 करोड़ का आवंटन किया गया है।

फसल अवशेष प्रबंधन

57. पराली जलाना राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और पंजाब सरकार इसे हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस मुद्दे को रोकने के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हमारे किसानों की भलाई दोनों सुनिश्चित हो सकें।

58. स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने भूसा आधारित बॉयलर की ओर बढ़ रहे उद्योगों को समर्थन देने के लिए ₹60 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी निर्धारित की है। इस पहल से प्रतिवर्ष 30 लाख टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है, जिससे वायु प्रदूषण पर काफी हद तक अंकुश लगेगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया, जिसमें 25 से अधिक हितधारकों ने पहले ही रुचि दिखाई है, बड़े पैमाने पर अपनाने की संभावना को उजागर करती है। यह नीति न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान करती है, बल्कि औद्योगिक नवाचार और पर्यावरणीय लचीलेपन को भी बढ़ावा देती है, जिससे पंजाब सतत् विकास में अग्रणी बन जाता है।

59. फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को सहायता देने के लिए ₹500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। सीआरएम मशीनों की खरीद (कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना) और धान पराली आपूर्ति श्रृंखला केंद्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसानों को प्रभावी अवशेष प्रबंधन पद्धतियों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता पहल की जाएगी।

किसानों को मुफ्त बिजली

60. राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹9,992 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है।

बागवानी

61. अध्यक्ष महोदय, कृषि और बागवानी विकास में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, पंजाब को 2023-24 के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार दिया गया है, जिसके पास देश में सबसे अधिक स्वीकृत प्राजैक्ट हैं।

62. राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक नई पहल प्रस्तावित है, जो शुरू में अमृतसर, एसबीएस नगर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और होशियारपुर जिलों को कवर करेगी और इस पहल में जागरूकता कार्यक्रम, क्लस्टर गठन, कृषि सखी सहायता, इनपुट संसाधन केंद्र, किसान प्रोत्साहन, प्रमाणन, प्रशिक्षण और स्टार्टर किट शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग की विभिन्न पहलों के लिए कुल ₹137 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मिट्टी एवं जल संरक्षण

अध्यक्ष महोदय,

63. संगरूर जिले में नहर सिंचाई को मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 38,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने और 20,000 किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की एक बड़ी पहल प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना को प्रारंभ करने के लिए ₹100 करोड़ का आवंटन

निर्धारित किया गया है।

64. इसके अतिरिक्त, फाजिल्का जिले में जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए एक नई परियोजना प्रस्तावित है, जबकि सिंचाई के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी प्रदान करने और कंडी क्षेत्र में जल संचयन परियोजनाओं को लागू करने के प्रयास भी किए जाएंगे, जिससे 30,000 हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा।

पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन

65. पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और पशुधन नस्लों में सुधार करने के लिए, हम पायलट परियोजना के रूप में छह जिला पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिकों में इन-पेशेंट वार्ड सेवाएं और ब्लू क्रॉस स्टोर शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹704 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

66. जलभराव वाले क्षेत्रों में झींगा पालन को बढ़ावा देने, किसानों के लिए राजस्व उत्पन्न करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक अत्याधुनिक झींगा प्रसंस्करण युनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सुविधा वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य में मौजूदा झींगा पालक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।

सहकारिता

67. पंजाब सरकार हमारे गन्ना किसानों को समर्थन देने के लिए दृढ़ है। 2024-25 पेराई सत्र के लिए, हमने देश में सबसे अधिक गन्ना खरीद मूल्य ₹401 प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी लंबित भुगतान पूरी तरह से चुका दिए गए हैं, जिससे हमारे किसानों को समय पर वित्तीय राहत सुनिश्चित हो रही है। हमारी सरकार इस सहायता को जारी रखने

के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹250 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

68. चीनी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, बटाला सहकारी चीनी मिल में ₹296 करोड़ की लागत से निर्मित 14 मेगावाट को-जन प्लांट के साथ 3500 टीसीडी चीनी प्लांट अब सफलतापूर्वक चालू हो गया है। राज्य में सतत ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाते हुए मिल में एक बायो-सीएनजी परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है।

69. इसके अलावा, दूध उत्पादकों को उचित लाभकारी दूध मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹100 करोड़ का आवंटन किया गया है तथा ₹75 करोड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए तथा ₹28 करोड़ पैक्स परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हैं, जिससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित होगा।

वानिकी एवं वन्यजीव

70. हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा राज्य में हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 3 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 29 लाख पौधे ट्यूबवेलों के आसपास लगाए गए हैं, जबकि पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में 268 नानक बगीची और 46 पवित्तर वन विकसित किए जा रहे हैं। पंजाब में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री आनंदपुर साहिब में जज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन पहलों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹281 करोड़ का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।

शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

71. मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब राज्य ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रतिष्ठित "सर्वश्रेष्ठ राज्य" पुरस्कार और होशियारपुर जिले के लिए "सर्वश्रेष्ठ जिला" पुरस्कार प्राप्त करके एक और मानक स्थापित किया है। यह पुरस्कार स्कूल समुदायों के बीच पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने में पंजाब के अनुकरणीय प्रयासों को दर्शाता है, तथा राष्ट्रव्यापी पहल में इसके नेतृत्व को मजबूत करता है।

72. राज्य के प्रमुख आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ.एल.एन) कार्यक्रम, मिशन समरथ ने छात्रों के बुनियादी कौशल को सफलतापूर्वक मजबूत किया है, जिससे 1.4 मिलियन बच्चे, 70,000 शिक्षक और 19,000 स्कूल लाभान्वित हुए हैं। इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों, अनुभवात्मक शिक्षण और उचित स्तर पर शिक्षण (TaRL) शिक्षण पद्धति पर ध्यान केंद्रित करके, इसने भाषा और गणित में प्राथमिक कक्षाओं में 15% और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 25% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

73. प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग में पंजाब भर में 21.81 लाख अभिभावकों ने अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनके समग्र विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा मिला। इस पहल ने अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल समुदाय के बीच के बंधन को मजबूत किया।

74. शिक्षा में उत्कृष्टता के हमारे प्रयास में, शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसीपलों, हेड-मास्टरों और शिक्षकों को कौशल उन्नयन के लिए प्रिंसिपल्स अकादमी, सिंगापुर; राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NIE) अंतर्राष्ट्रीय, सिंगापुर; टुर्कु विश्वविद्यालय, फिनलैंड; और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा गया। इस पहल का उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना

है, ताकि शिक्षकों को उन्नत शिक्षण पद्धतियां लाने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे हमारे छात्रों को लाभ होगा और राज्य में शिक्षा की नींव मजबूत होगी।

75. इस सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की सफलता के आधार पर, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹17,975 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो कुल व्यय का लगभग 12% है।

स्कूल शिक्षा

76. अध्यक्ष महोदय, हम पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के अपने दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बच्चे 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान, कौशल और अवसरों से सुसज्जित हों। हमारी पहल शैक्षिक उत्कृष्टता के चार स्तंभों - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास, सतत बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास पर आधारित है - जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य मिले।

i. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** स्कूल ऑफ एमिनेंस और स्कूल ऑफ ब्रिलियंस उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जो सहकर्मी सिखलाई और अकादमिक मज़बूती को बढ़ावा देंगे। स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग स्कीम छात्रों को आजीविका के अवसरों के लिए तकनीकी कौशल से लैस करेगी, जबकि मिशन समरथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्रों में आवश्यक दक्षताओं को विकसित करेगा।
ii. **समग्र विकास:** 425 प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल आफ़ हैप्पीनेस में तबदील किए जा रहे हैं, ताकि हवादार कक्षा-कक्ष, खेल के मैदान और एक्टिविटी कार्नर वाले पोषणकारी वातावरण का निर्माण किया जा सके। पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम जैसी पहल छात्रों में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देगी।

iii. **बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन:** बिजली की लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 4,098 सरकारी स्कूलों में सौर पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं, तथा आगे भी इनके विस्तार की योजना है। चारदीवारी और रखरखाव अनुदान सहित बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन से विशेष रूप से छात्राओं के लिए सुरक्षित और अच्छी तरह से अनुरक्षित स्कूल सुनिश्चित होंगे।

iv. **समावेशी विकास:** सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए एक समर्पित वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कैंपस मैनेजर, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार और सफाईकर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा अभियान ₹1240 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण योजना ₹466 करोड़, निःशुल्क पुस्तकें ₹75 करोड़, तथा पूर्व-प्राथमिक छात्रों के लिए यूनिफॉर्म ₹35 करोड़ जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सुलभ एवं समतामूलक शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

77. इस समग्र दृष्टिकोण के साथ, हम पंजाब के शैक्षिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधारशिला रख रहे हैं - यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे छात्र अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करें, आवश्यक जीवन कौशल विकसित करें, और आधुनिक दुनिया में नेतृत्व करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।

उच्च शिक्षा

78. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, फ़ैक्लटी प्रशिक्षण को बढ़ाने, छात्र सुविधाओं को उन्नत करने और परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के लिए एक गतिशील वातावरण तैयार हो सके।

79. इस दृष्टिकोण को और मजबूत करने के लिए, प्रमुख पहलों के लिए बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना के अंतर्गत ₹199 करोड़ और बुनियादी ढांचे के उन्नयन, खेल सुविधाओं, पुस्तकालयों और कौशल-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए ₹160 करोड़ शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षा

80. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजाब के युवाओं को गतिशील रोजगार मार्केट के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और उद्योग-सम्बंधित कौशल से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2024-25 सत्र में, हमने 137 सरकारी आईटीआई में रिकॉर्ड 93.04% दाखिला दर हासिल की, जिसमें 32,827 प्रशिक्षुओं ने दाखिला लिया - 5,000 नई सीटों के बढ़ने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 17% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

81. उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटने के लिए, हमने पुराने पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया है तथा अत्याधुनिक, उद्योग-उन्मुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक उद्योग अनुभव को जोड़ने करने के लिए प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डी.एस.टी) का विस्तार किया है। तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी जा रही है, आईटीसी और स्वराज इंजनस द्वारा समर्थित आई.टी.आई (महिला) में इंजीनियरिंग ट्रेड पाठ्यक्रमों को राज्यव्यापी विस्तार दिया जाएगा।

82. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, न्यू एज पाठ्यक्रमों के लिए उन्नत मशीनरी खरीदने और चल रही निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹579 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इस पहल के तहत एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ₹33 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान

83. "सीएम दी योगशाला" पहल के तहत, प्रतिदिन 3,200 योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं। एक समर्पित योग प्रशिक्षक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसमें 2,630 प्रशिक्षुओं को नामांकित किया गया है, और लगभग दो लाख लोगों तक दैनिक योग सत्र का विस्तार करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

84. वित्तीय वर्ष 2025-26 में, शहीद भगत सिंह (एस.बी.एस) नगर के बरनाला कलां गांव में 50 एम.बी.बी.एस सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन विभिन्न पहलों को शुरू करने के लिए ₹1336 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है।

विश्वविद्यालयों और घटक कालेजों को ग्रांट-इन-एड

85. हमारी सरकार विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों जैसे गडवासु, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, जी.एन.डी.यू तथा अन्य के साथ-साथ उनके घटक कॉलेजों के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1650 करोड़ का बजट प्रावधान निर्धारित किया गया है।

रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण

86. पंजाब के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। इस साल, 1,468 जॉब फेयर्स के माध्यम से 85,248 उम्मीदवारों को नौकरी मिली, जबकि 24,345 व्यक्तियों को स्वरोजगार ऋण प्राप्त हुआ। अप्रैल 2022 से अब तक नियमित सरकारी भर्ती के तहत 51,655 नियुक्ति पत्र

जारी किए जा चुके हैं। पंजाब को अपने युवा उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं पर भी बहुत गर्व है - 22 कैडेट एन.डी.ए और अन्य अकादमियों में शामिल हो गए हैं, 18 को अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया है, और 47 कैडेटों ने 74.60% की असाधारण सफलता दर के साथ एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो देश में सर्वोच्च है। मैं कौशल प्रशिक्षण और करियर परामर्श के माध्यम से रोजगार क्षमता को और बढ़ाने के लिए ₹230 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले

माननीय अध्यक्ष महोदय,

87. पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सम्मानित करने और प्रदर्शित करने के लिए, सरकार ने ₹33 करोड़ की लागत से राम तीर्थ, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि पैनोरमा की स्थापना की है। 14 गैलरियों वाला यह अत्याधुनिक संग्रहालय आधुनिक तकनीक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के जीवन, शिक्षाओं और योगदान को प्रस्तुत करता है। 7 अक्टूबर, 2024 को उद्घाटन किए गए इस पैनोरमा ने हजारों भक्तों को आकर्षित किया है और उन्हें एक गहन और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान किया है।

88. श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के सम्मान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य स्तर पर स्मारक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, साथ ही गुरु साहिब की यात्राओं से जुड़े स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा स्थापित शहर श्री आनंदपुर साहिब के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, इसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए ₹10 करोड़ का विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा।

89. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने शहीद भगत सिंह नगर में ₹54 करोड़ की लागत से हेरिटेज स्ट्रीट और सभागार बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, राज्य भर में 32 सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर नाटक आयोजित किए जाएंगे, जो पंजाब के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न पहलों को शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹204 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है।

गृह मामले, न्याय एवं जेल

90. माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की रहनुमाई में 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स (एस.एस.एफ) ने पंजाब में सड़क सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाया है। ये टीमें 6-8 मिनट के भीतर आपातकालीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करती हैं, ज़रूरी प्राथमिक उपचार प्रदान करती हैं और अस्पताल तक त्वरित परिवहन प्रदान करती हैं। इन सक्रिय उपायों के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में उल्लेखनीय 48% की कमी आई है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। गृह, न्याय एवं जेल विभाग के लिए ₹11,560 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है।

91. इसके अलावा, राज्य ने जेल प्रबंधन और कैदी-कल्याण को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख सुरक्षा और पुनर्वास उपायों को लागू किया है। अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए केंद्रीय जेलों में एआई-संचालित सीसीटीवी निगरानी की तैनाती की जा रही है, साथ ही 12 संवेदनशील जेलों में वी-कवच जैमर का विस्तार किया जा रहा है। कैदियों के पुनर्वास पर जोर देते हुए 2,200 से अधिक कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित किया गया है, जबकि 513 कैदियों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। राज्य में जेल बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव है।

92. माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण और उन्नत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ₹233 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। इसमें पुलिस परिसरों, पुलिस लाइनों, पुलिस स्टेशनों के निर्माण और नवीनीकरण और पुलिस कर्मियों के आवास के लिए भूमि की खरीद शामिल है।

93. राज्य के न्यायिक बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए, हम वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹132 करोड़ की अनुमानित लागत से डेराबस्सी, खन्ना और पातड़ां में न्यायालय परिसरों के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं।

बुनियादी ढाँचा

सड़कें और पुल

94. माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष के दौरान हमने ₹1,082 करोड़ की कुल लागत से 1,444 किलोमीटर सड़कें सफलतापूर्वक पूरी की हैं तथा 20 पुलों का निर्माण किया है। बुनियादी ढांचे के इस विस्तार से कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है, जिससे यात्रियों, किसानों और व्यवसायों को लाभ हुआ है, साथ ही आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिला है।

95. वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित कार्य किये जाने का प्रस्ताव है:

i. **सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाना:** 2718 किलोमीटर योजना सड़कों और नए संपर्क मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए नाबार्ड के तहत ₹855 करोड़।
ii. **पुल के बुनियादी ढांचे में वृद्धि:** नये पुलों के निर्माण और निर्माणाधीन पुलों के पूरा होने के लिए ₹155 करोड़ आवंटित किये गये हैं।

iii. **प्रमुख बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** 200 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन और पांच पुलों के निर्माण, जिनमें से तीन सेतु बंधन के अधीन हैं, के लिए सीआरआईएफ के तहत ₹190 करोड़।

iv. **ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना:** पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 1,300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए ₹600 करोड़।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

96. मैं सतही जल आधारित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, पुराने बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1614 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें राज्य के 176 गांवों में पाइप जलापूर्ति को अपग्रेड करने/उपलब्ध कराने तथा बेहतर सेवा वितरण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है।

जल संसाधन

97. रावी नदी पर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पहल, शाहपुर कंडी बांध परियोजना, तेजी से आगे बढ़ रही है, तथा मुख्य बांध का निर्माण अब पूरा हो गया है। अब तक ₹2,604 करोड़ के निवेश के साथ, इस परियोजना से 1,042 एमयू जलविद्युत उत्पन्न होगी और अमृतसर में अपर बारी दोआब नहर (यूबीडीसी), गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट में 1.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, जल प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जालंधर में ₹34 करोड़ की लागत से काला सिंघा ड्रेन लाइनिंग परियोजना पर काम चल रहा है।

98. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हम रूपनगर, एसबीएस नगर, होशियारपुर, एसएएस नगर और पठानकोट में 40 गहरे ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव रखते हैं, साथ ही सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पास 167 उथले ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव रखते हैं।

इन पहलों से ₹85 करोड़ की कुल लागत से 7,877 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई बढ़ेगी, जिससे जल संकट वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

99. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और नहर सिंचाई का विस्तार करने के लिए, सरकार ने राज्य भर में जलमार्गों की लाइनिंग और पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन परियोजनाओं के अंतर्गत ₹315 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 63,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाना भी शामिल है।

100. भूजल दोहन 166% तक पहुंच जाने तथा 153 में से 117 ब्लॉकों के अत्यधिक दोहन के कारण पंजाब गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पहले से वंचित क्षेत्रों में नहर सिंचाई का विस्तार करने के लिए ₹8,227 करोड़ की सतही जल परियोजनाओं की पहचान की है। स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

101. माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए जलमार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार तथा विभिन्न जिलों में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने सहित नई परियोजनाओं के लिए ₹723 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के लिए, मैं ₹3,246 करोड़ के कुल बजट आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹1,343 करोड़ शामिल हैं, जिससे महत्वपूर्ण जल बुनियादी ढांचे की पहल की निरंतर प्रगति सुनिश्चित होगी।

खनन

102. अध्यक्ष महोदय, अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए हमने 74 सार्वजनिक खनन स्थलों का संचालन शुरू किया है, 91.21 लाख मीट्रिक टन सामग्री बेची गई तथा

वाणिज्यिक खनन स्थल नीलामी के अंतर्गत 39 क्लस्टरों का सफलतापूर्वक आवंटन करते हुए टिकाऊ और विनियमित विकास को बढ़ावा दिया है।

103. अवैध खनन पर निगरानी बढ़ाने और अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है और प्रतिस्पर्धी दरों पर इसके क्रियान्वयन के लिए चार कंपनियों को पैनल में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे अवैध खनन गतिविधियों की फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग की जा सकेगी। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर खनन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अधिक स्थलों को शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं।

राजस्व वृद्धि एवं पूंजी सृजन

104. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,11,740 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें स्वयं कर राजस्व ₹63,250 करोड़ होगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों का हिस्सा ₹25,703 करोड़ और केंद्र से अनुदान सहायता ₹10,576 करोड़ निर्धारित की गई है।

105. पिछले तीन वर्षों में मुझे आबकारी एवं कराधान विभाग की देखरेख करने का सौभाग्य मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हमारा उत्पाद शुल्क राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में, जब हमने कार्यभार संभाला था, ₹6,254 करोड़ से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष में ₹10,350 करोड़ हो गया है, जो 63% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय प्रगति हमारी पार्टी के ईमानदार शासन और सरदार भगवंत सिंह मान जी के गतिशील नेतृत्व का प्रमाण है। आगे बढ़ते हुए, हमने अगले वित्तीय वर्ष के लिए ₹11,200 करोड़ का महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे निरंतर राजकोषीय मजबूती और

आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

106. राजस्व वृद्धि के ये उपाय सिर्फ़ एक कर या विभाग तक सीमित नहीं हैं। हमारे जी.एस.टी. संग्रह में 62% की वृद्धि की उम्मीद है, जो ₹15,542 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22) से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष में ₹25,200 करोड़ होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय वृद्धि बहुआयामी रणनीतियों का परिणाम है, जिसमें परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ हमारा सहयोग, एसआईपीयू (राज्य खुफिया और निवारक इकाई) और टीआईयू (कर खुफिया इकाई) को मजबूत करना, और "बिल लियाओ, इनाम पाओ" जैसी नागरिक-केंद्रित पहलों को आरंभ करना शामिल है।

107. इस गति को आगे बढ़ाते हुए, हमने अगले वित्तीय वर्ष के लिए ₹27,650 करोड़ का महत्वाकांक्षी जीएसटी संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया है - जो अब तक का उच्चतम अनुमान है - जो मजबूत आर्थिक प्रशासन और राजस्व वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

108. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कर नीतियां व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसके प्रमाण के रूप में, हमारी सरकार ने पुरानी वैट व्यवस्था के तहत बकाया राशि का समाधान करने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति शुरू की। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई इस योजना को उद्योग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसके तहत 70,311 डीलरों को बकाया कर देनदारियों में ₹867 करोड़ की छूट का लाभ मिला। इसके अलावा, इस पहल से राज्य के खजाने में ₹164 करोड़ की उल्लेखनीय वसूली हुई, जो पिछली सरकार द्वारा दो ओटीएस योजनाओं के माध्यम से एकत्र किए गए मात्र ₹13 करोड़ से कहीं अधिक है। यह सफलता निष्पक्ष और व्यावहारिक कर सुधारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो राज्य के लिए राजस्व दक्षता सुनिश्चित करते हुए व्यवसायों को समर्थन प्रदान करते हैं।

109. स्टाम्प और पंजीकरण राजस्व में भी 87% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जो पिछले तीन वर्षों में ₹3,308 करोड़ से बढ़कर ₹6,200 करोड़ होने की उम्मीद है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, विभाग का राजस्व ₹7,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो चालू वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

110. इन सभी राजस्व वृद्धि उपायों के परिणामस्वरूप हमारा स्वयं का कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹37,327 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹57,919 करोड़ होने का अनुमानहै, यानी हमारी सरकार के केवल 3 वर्षों में ₹20,500 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए यह आँकड़ा अब तक के उच्चतम ₹63,250 करोड़ होने का अनुमान है। इस राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋण समेकन हुआ है तथा राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात अगले वर्ष 44.77 प्रतिशत से घटकर 44.50 प्रतिशत होने का अनुमान है।

111. वित्तीय विभाग ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पेंशन सुधार किए हैं। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर "पेंशन सेवा पोर्टल" का शुभारंभ है, जिसे पेंशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और 3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

112. हमारे कर्मचारी हमारे प्रशासन की रीढ़ हैं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने उनके उचित हकों को देने में देरी की, हमने इस लम्बे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने कर्मचारियों के छठा वेतन आयोग के बकाया ₹14,191 करोड़ के भुगतान के लिए एक संरचित परिसमापन योजना लागू की है, जिससे हमारे 6 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे लाभ होगा और ये भुगतान चालू वित्तीय वर्ष से ही शुरू हो चुके हैं।। यह सिर्फ़ वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि उनकी अमूल्य सेवा की मान्यता है।

113. माननीय अध्यक्ष जी, पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम पांच वर्षों के दौरान वास्तविक औसत वार्षिक पूंजीगत व्यय केवल ₹3,800 करोड़ था, जो कि बहुत छोटा आंकड़ा है और इसलिए दीर्घकालिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा डालता है। इस उपेक्षा के स्थाई रूप से बुरे परिणाम आए, जिससे प्रगति धीमी हो गई तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर सीमित हो गए। हमारी सरकार निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ₹10,302 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्तमान वर्ष के ₹8,347 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि है। यह प्रमुख प्रस्ताव मजबूत बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास को गति देगा और हमारे राज्य के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

माननीय अध्यक्ष महोदय,

114. मुझे पूरा विश्वास है कि यह "बदलता पंजाब" बजट एक समृद्ध और आत्मनिर्भर पंजाब की नींव को और मजबूत करेगा। मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक के दूरदर्शी मार्गदर्शन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के गतिशील नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दृढ़ प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी बदलाव की इस लहर को आगे बढ़ाने में सदा सहायक रही है।

115. मैं इस अवसर पर वित्तीय और योजना विभागों के समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास इस व्यापक और दूरदर्शी बजट को तैयार करने में सहायक रहे हैं।

116. मैं अब इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिंद